भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 220

03 फरवरी, 2021 को उत्तर के लिए

अधिकारहीन वर्गों के लोगों को स्मार्ट सिटी मिशन का लाभ प्रदान किया जाना

220 श्री संजय सिंहः

क्या ***आवासन और शहरी कार्य*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वीकृत और पूरी की गई 'स्मार्ट सिटी' परियोजनाओं की संख्या कितनी है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं का कुल व्यय कितना है; और

(ग) नगरों और शहरी क्षेत्रों में अत्यंत अधिकारहीन और निम्न आय वर्ग के लोगों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) और (ख): भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी के रूप में 100 शहरों के विकास के लिए 25 जून, 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) की शुरूआत की थी। जनवरी 2016 से जून 2018 तक 4 चरणों की चयन प्रक्रिया पूरी करके 100 स्मार्ट सिटी का चयन किया गया है। 100 स्मार्ट सिटी के लिए 2,05,018 करोड़ रू. की कुल 5,151 परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनके लिए उनके स्मार्ट सिटी प्रस्ताव (एससीपी) कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में पड़े है। अपेक्षा है कि स्मार्ट सिटी अपने चयन की तारीख से पांच वर्षों के अन्दर अपनी परियोजनाएं पूरी कर लेंगे।

22 जनवरी, 2021 की स्थिति के अनुसार, 1,76,908 करोड़ रु. (86%) की 5,416 परियोजनाओं के लिए निविदाएं जारी की गई हैं, जिनमें से 1,41,600 करोड़ रू. (69%) की 4,628 परियोजनाओं का कार्यान्वयन चल रहा है/पूरा हो गया है। केंद्र सरकार ने 100 स्मार्ट सिटी के लिए केंद्रीय हिस्से के रूप में 22,822.33 करोड़ रू. की धन राशि जारी की है, जिसमें से स्मार्ट सिटीज ने 18,403 करोड़ रु. (81%) का उपयोग किया है।

(ग): एससीएम के अन्तर्गत, सतत और समावेशी विकास पर जोर दिया जाता है। मिशन का उद्देश्य स्थानीय क्षेत्र का विकास और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आर्थिक विकास करना और लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। एससीएम में द्विस्तरीय कार्यनीति-क्षेत्र आधारित विकास (एबीडी) और पैन सिटी विकास को अपनाया गया है। एबीडी के अन्तर्गत, एक या अधिक हरित क्षेत्र/रेट्रोफिटिंग/पुनर्विकास मॉडल के माध्यम से भौतिक, सामाजिक, संस्थागत और आर्थिक अवसंरचना के व्यापक विकास के लिए सघन क्षेत्रों में कार्य किया जाता है। पैन सिटी विकास के अन्तर्गत केवल समेकित कंमाड और नियंत्रण केंद्र, ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन के लिए स्मार्ट समाधान, पार्किंग, स्वच्छ पर्यावरण, बाढ़ प्रबंधन, शासन और नागरिक सेवा में सुधार इत्यादि तक सीमित न रखते हुए ऐसे घटकों सहित शहर-वार तरीके से स्मार्ट समाधान के अनुप्रयोग की परिकल्पना की गई है। मिशन विविध क्षेत्रों जैसे गतिशीलता, निर्मित पर्यावरण, गैर-मोटरीकृत और सार्वजनिक परिवहन, जल और अपशिष्ट जल, नवीकरणीय उर्जा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, किफायती आवास, नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। क्षेत्र आधारित और पैन-सिटी दृष्टिकोण के संयोजन के माध्यम से किए गए व्यापक विकास से जीवन की गुणवत्ता बेहतर होगी, रोजगार का सृजन होगा और सबकी विशेषतौर पर शहरों और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले अत्यंत उपेक्षित और निम्न आय समूहों की आय में वृद्धि होगी।

****